



फिर से फैशनेबल योजनाओं का निर्माण

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III
(भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक - जयन जोस थॉमस (शिक्षक, अर्थशास्त्र,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली)

04 दिसंबर, 2018

“आर्थिक निर्णय लेने से भारतीय राज्यों को बाहर रखने का परिणाम उद्योगों पर पड़ता है।”

आर्थिक योजना को आज फैशनेबल नहीं माना जाता है। फिर भी, समकालीन आर्थिक चर्चाओं को विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू द्वारा समर्थित योजनाओं की समीक्षा करके लाभ प्राप्त होगा।

जैसा कि अच्छी तरह से जाना जाता है, नेहरू के नेतृत्व में भारत ने 1950 के दशक की शुरुआत में देश के औद्योगिकीकरण की रणनीति का उद्घाटन किया। इसमें विनिर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों (पीएसयू) की स्थापना, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे समय की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) सहित उच्च शिक्षा के केंद्रों की स्थापना भी शामिल थी और ये सब उस गरीब देश ने संभव बनाया, जो अभी भी स्वतंत्रता के शुरुआती सालों के दौरान कई समस्याओं से जूझ रहा थी।

रूढ़िवाद चुनौतीपूर्ण

लेकिन इसका अंत यही तक नहीं था। मशीन निर्माण और परमाणु अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में जानबूझ कर प्रवेश करते हुए, जिसमें श्रम से अधिक पूंजी और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है, भारत भी आर्थिक सिद्धांत में गहराई से रूढ़िवादी रूप से चुनौती दे रहा था। डेविड रिकार्डो के समय से, अर्थशास्त्रियों की एक आकाशगंगा ने तर्क दिया था (और कई अभी भी इस पर बहस करते हैं) कि देशों को उनके तुलनात्मक लाभ के आधार पर उद्योगों को विकसित करना चाहिए।

इस सिद्धांत के अनुसार, भारत जैसे श्रम-अधिशेष देश को वस्त्रों या चमड़े जैसे श्रम-केंद्रित क्षेत्रों में अपनी औद्योगिक विकास की महत्वाकांक्षाओं को सीमित करना चाहिए। आखिरकार, सिद्धांत यह अवश्य पूछेगा कि भारत जैसे देश को मशीनों या फार्मास्यूटिकल्स का घरेलू उत्पादन क्यों करना चाहिए, जब ऐसे उत्पादों को आसानी से उन्नत देशों से आयात किया जा सकता है?

औपनिवेशिक काल के दौरान, भारत में ब्रिटिश सरकार वास्तव में तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत को अभ्यास में ला रही थी, जो अधिकांश भारतीयों के नुकसान के लिए था। अपनी पुस्तक 'द डिस्कवरी ऑफ इंडिया' में, नेहरू ने बताया कि कैसे औपनिवेशिक सरकार ने व्यवस्थित रूप से भारतीय उद्यमशीलता को झुकाया। 1940 के दशक की शुरुआत में अहमदनगर किले में अपनी कोठरी से लिखते हुए नेहरू ने तर्क दिया था कि आधुनिक भारत के लिए मूलभूत आवश्यकताओं में एक हैवी इंजीनियरिंग और मशीन बनाने के उद्योग, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान और विद्युत शक्ति शामिल है।

देश की सामान्य गरीबी के बावजूद, 1950 के दशक से भारत में शुरू किया गया कार्यक्रम पूंजी और प्रौद्योगिकी केंद्रित क्षेत्रों में स्वदेशी क्षमताओं का निर्माण करने के लिए, अन्य विकासशील और तीसरे विश्व राष्ट्रों के लिए एक मॉडल बन गया। भारतीय योजनाओं के आसपास की बहस ने अर्थशास्त्र के विकास के लिए एक उप-अनुशासन के रूप में एक उपजाऊ लॉन्चिंग पैड प्रदान किया।

यहाँ केवल यह तर्क उचित होगा कि योजना के शुरुआती वर्षों के दौरान ही भारत के विविध आर्थिक आधार के लिए नींव रखी गई थी। आज जो भारत सूचना प्रौद्योगिकी और ज्ञान-केंद्रित क्षेत्रों में अपनी सफलताओं का आनंद उठा रहा है उसकी नींव शुरुआती दशकों में स्थापित किये गये अनुसंधान और शैक्षिक संस्थानों द्वारा स्थापित की गयी थी।

हालाकि, इसी दौरान कृषि और लघु उद्योगों के विकास में बाधाओं को दूर करने के लिए योजनाओं ने ज्यादा मदद नहीं की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधारों को लागू करने और सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत का रिकॉर्ड अप्रत्याशित रहा है। नतीजतन, राज्य के नेतृत्व वाले विकास से लाभ अब तक बहुत ही कम भारतीयों तक पहुँच सका है।

योजना के माध्यम से विकास की दिशा में भारत की वचनबद्धता 1990 के दशक से ही कम हो गई थी और यह वर्ष 2014 में योजना आयोग को औपचारिक रूप से नष्ट करने से पहले ही शुरू हो गयी थी। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों के परिचय के बाद, देश में सार्वजनिक निवेश, विशेष रूप से कृषि और उद्योग पर गिरावट आई है।

इसके अलावा, पीएसयू केवल वाणिज्यिक संस्थाओं के रूप में लाए जाने वाले रिटर्न के लिए मूल्यवान हैं। पीएसयू नई प्रौद्योगिकियों और ज्ञान के रचनाकारों के रूप में ज्यादा मददगार नहीं हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ निजी क्षेत्रों की रुचि या क्षमता कम हो।

बेहतर योजना बनाने की उपेक्षा करने से और आर्थिक निर्णय लेने में राज्यों को दूर रखने से भारतीय उद्योगों पर गंभीर प्रभाव पड़े हैं। भारत आज वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है, चाहे वह यात्री कार हो, मोबाइल फोन या कोई अन्य खाद्य उत्पाद हो। इस तरह के बड़े घरेलू बाजार के उद्भव के बावजूद, देश में बड़े श्रम भंडार को अवशोषित करने में भारतीय विनिर्माण का रिकॉर्ड अबाध बना हुआ है। मशीनरी, परिवहन उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामान और उनके सभी घटकों के आयात 2000 के बाद से भारत में लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही 'मेक इन इंडिया' पहल की शुरुआत के बाद भी यह प्रवृत्ति ज्यों के त्यों कायम है।



एक वैश्वीकृत दुनिया में योजना का निर्माण

योजना बाजार और वैश्वीकरण के साथ असंगत नहीं है। इसके विपरीत, एक विकासशील देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्याप्त हलचल के बीच आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें औद्योगिक नीतियों के मार्गदर्शन की काफी आवश्यकता होगी। विनिर्माण में दक्षिण कोरिया जैसे पूर्वी एशियाई देशों द्वारा हासिल की गई सफलताएं काफी हद तक उनकी सरकारों द्वारा कई दशकों में रणनीतिक योजना का परिणाम हैं।

चीन धीरे-धीरे कम मजदूरी उद्योगों से अपने आर्थिक आधार को स्थानांतरित कर रहा है और अब कृत्रिम बुद्धि और नवीकरणीय ऊर्जा समेत कई नई प्रौद्योगिकियों में, अमेरिका से भी आगे निकलते हुए वैश्विक लीडर के रूप में उभर रहा है। विशेष रूप से चीन की इन उपलब्धियों के लिए सबसे अधिक श्रेय इसकी सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बनाई गई योजना और निवेश का है।

भारत की रोजगार चुनौती, जो हर साल औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों, दोनों में करीब 15 मिलियन के करीब पहुँच चुका है, दुनिया में किसी भी अन्य देश (चीन को छोड़कर) से कहीं अधिक बड़ी है और इसे उन प्रौद्योगिकियों के साथ हल नहीं किया जा सकता है, जो विदेशी कंपनियां भारत में लाती हैं और जिससे श्रम की बचत होती है।

दूसरी तरफ, भारत को नई प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, जो नए आर्थिक अवसर का सृजन करेगी और श्रम को खत्म नहीं, बल्कि उसे अवशोषित करेंगी। उदाहरण के लिए, बायोटेक्नोलॉजी में मिली हमारी सफलताओं को देखें, जो हमारे कृषि उत्पादों या इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों के लिए नए वाणिज्यिक अनुप्रयोग का निर्माण कर सकती हैं और साथ ही इससे हमें आयातित सामग्रियों पर कम निर्भर रहना होगा।

भारत के शोध संस्थान और हमारे पीएसयू को ऐसी प्रौद्योगिकियों के निर्माण और प्रसार में संलग्न होना चाहिए। देश की औद्योगिक नीतियों को नए रोजगार बनाने के लिए इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को शिक्षित कर उन्हें और सक्षम बनाना चाहिए और इन सभी को सफल बनाने के लिए हमारी आर्थिक चर्चाओं के केंद्र में योजना को वापस लाया जाना चाहिए।

GS World वीए...

औद्योगीकरण

क्या है?

- औद्योगीकरण एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया का नाम है। इसमें मानव-समूह की सामाजिक-आर्थिक स्थिति बदल जाती है, जिसमें उद्योगों का बोलबाला होता है।
- वस्तुतः यह आधुनिकीकरण का एक अंग है।
- बड़े-पैमाने की उर्जा-खपत, बड़े पैमाने पर उत्पादन, धातुकर्म की अधिकता आदि औद्योगीकरण के लक्षण हैं।
- एक प्रकार से यह निर्माण कार्यों को बढ़ावा देने के हिसाब से अर्थप्रणाली का बड़े पैमाने पर संगठन है।

पृष्ठभूमि

- पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में प्रमुख औद्योगिक बदलाव 18 वीं और 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति के दौरान हुआ।
- आर्थिक इतिहासकार चार महत्वपूर्ण राष्ट्रीय औद्योगीकरणों को इंगित करते हैं: ग्रेट ब्रिटेन में 1760 और 1860 के बीच मूल औद्योगिकीकरण, 1790 से 1870 तक संयुक्त राज्य में औद्योगिकीकरण, जापान में 1880 और 1970 के बीच बेजोड औद्योगिक लाभ, और 1960 तक समकालीन समय तक चीन में औद्योगिकीकरण।

नगरीकरण और आर्थिक विकास में संबंध

- किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के निम्नलिखित तीन लक्षण मुख्य होते हैं-

- प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ताकि लोगों का जीवन स्तर उन्नत हो सके।
- निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या में कमी।
- बेरोजगार की दर एवं आकार में कमी।
- आंकड़ों के आधार पर जब कुल जनसंख्या में नगर जनसंख्या के अनुपात और प्रति व्यक्ति आय में संबंध गुणांक निकाला जाता है, तो वह 0.5 आता है।
- इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नगरीकरण और प्रति व्यक्ति आय में सकारात्मक संबंध है। किंतु यही सहसंबंध गुणांक जब जनसंख्या और दैनिक स्थिति बेरोजगारी के बीच निकाला जाता है, तो वह 0.18 आता है जो यह संकेत करता है कि नगरीकरण के परिणामस्वरूप बेरोजगारी में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं हुई।
- हानि
- बढ़ते औद्योगीकरण से वातावरण में प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि पर्यावरण के संतुलन का खतरा मँडराने लगा है।
- औद्योगिक विकास का सबसे अधिक प्रभाव महानगरों एवं अन्य घनी आबादी वाले शहरों में देखने को मिलता है।
- शहरों व महानगरों में जनसंख्या घनत्व अधिक होने से मोटर वाहनों, गाड़ियों व दुपहिया वाहनों आदि की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है।
- यातायात के साधनों के अतिरिक्त बड़े-बड़े कारखाने, मिलें आदि न केवल वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं अपितु जल प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण आदि के लिए भी उत्तरदायी हैं।



- कल-कारखानों से निकला रासायनिक अवशेष पानी के साथ बहकर नदियों में प्रक्षेपित हो जाता है, जिससे स्वच्छ जल प्रदूषित हो जाता है।
- जिसके फलस्वरूप मनुष्य को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पाता है तथा साथ ही जलीय जंतुओं का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है।

चौथी औद्योगिक क्रांति या उद्योग 4.0

- यह एक सामूहिक शब्द है, जो समकालीन स्वचालन, डाटा एक्सचेंज और विनिर्माण प्रौद्योगिकी को समाविष्ट करता है तथा

जिस तरह से वर्तमान समय में व्यवसाय संपन्न हो रहे हैं, उनमें मूलभूत परिवर्तन को भी इंगित करता है।

- यह उन नवाचारों और प्रौद्योगिकियों के क्रांतिकारी प्रयोगों को संदर्भित करता है, जो भौतिक, डिजिटल तथा जैविक क्षेत्रों के बीच की रेखा को धूमिल कर रहे हैं।
- उदाहरण के लिए-चालक विहीन कारें, स्मार्ट (आकर्षक) रोबोटिक्स, कठोर और हल्के पदार्थ, 3डी प्रिंटिंग (छपाई) तकनीक का उपयोग करने वाली विनिर्माण प्रक्रियाएं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा इंटरनेट ऑफ सर्विसेज।

संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा

- निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-
 - मशीन निर्माण और परमाणु अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में श्रम से अधिक पूंजी और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है।
 - एडम स्मिथ जैसे अर्थशास्त्रियों का विचार था कि किसी देश को उनके तुलनात्मक लाभ के आधार पर उद्योगों को विकसित करना चाहिए।
 - औद्योगिकीकरण ना सिर्फ सामाजिक अपितु आर्थिक प्रक्रिया है।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य नहीं है/हैं?
- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

मुख्य परीक्षा

- 'औद्योगिकीकरण' एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया का नाम है, जिसमें उद्योगों का बोलबाला होता है। यह आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक है? साथ ही इसके नकारात्मक प्रभावों की भी चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

नोट : 03 दिसंबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d) होगा।

